

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1034

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

ऋण-जीडीपी अनुपात

1034. श्री सुब्बारायण के.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश का ऋण-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2018-19 में 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 56.8 प्रतिशत हो गया है;
- (ख) यदि हां, तो देश के कुल ऋण का ब्यौरा क्या है और 2018-19 से ऋण-जीडीपी अनुपात का प्रतिशत क्या है;
- (ग) वर्ष 2018-19 से अब तक की अवधि के लिए विदेशी ऋण और विदेशी ऋण-जीडीपी अनुपात का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार ऋण-जीडीपी अनुपात को प्रतिवर्ष कम से कम एक प्रतिशत कम करने का है जब तक कि यह एक स्थायी अनुपात तक नहीं पहुंच जाता; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है तथा स्थायी ऋण-जीडीपी अनुपात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): वर्ष 2018-19 से केंद्र सरकार के ऋण और ऋण-जीडीपी अनुपात का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	केन्द्र सरकार का ऋण	
	राशि (₹ लाख करोड़)	(जीडीपी का %)
2018-19	93.26	49.3
2019-20	105.07	52.3
2020-21	121.86	61.4*
2021-22	138.66	58.8
2022-23	156.02	57.9
2023-24	171.70	58.1
2024-25(आरई)	185.11	57.1
2025-26 (बीई)	200.16	56.1

* कोविड-19 महामारी का प्रभाव

(ग): वर्ष 2018-19 से बाह्य ऋण और बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	बाह्य ऋण (वर्तमान विनिमय दर)	
	राशि (₹ लाख करोड़)	(जीडीपी का %)
2018-19	4.74	2.5
2019-20	5.44	2.7
2020-21	6.15	3.1
2021-22	6.58	2.8
2022-23	7.48	2.8
2023-24	7.96	2.7
2024-25 (आरई)	8.46	2.6
2025-26 (बीई)	8.92	2.5

(घ) और (ङ): वित्त वर्ष 2024-25 (नियमित बजट) के बजट भाषण में केंद्र सरकार ने मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति संबंधी दृष्टिकोण के लिए रूपरेखा तैयार की है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को जीडीपी अनुपात में इस स्थिति पर बनाए रखना है कि ऋण और जीडीपी के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति रहे। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के एफआरबीएम दस्तावेजों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किसी भी बड़े मैक्रो-इकोनॉमिक विघटनकारी प्रतिकूल प्रभाव (प्रभावों) के बिना, और संभावित विकास प्रवृत्तियों और उभरती विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार का प्रयास प्रत्येक वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक) राजकोषीय घाटे को इस स्तर पर रखने का है कि 31 मार्च 2031 तक करीब 50±1 प्रतिशत के जीडीपी स्तर में ऋण को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के ऋण में गिरावट की प्रवृत्ति हो।
